

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 385]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 अगस्त 2023 — श्रावण 16, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2023

अधिसूचना

क्रमांक 9051/Rules/2023. — छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के अनुमोदन से, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नियम एवं आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, —

अध्याय 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“अध्याय — 9 (क)

फास्टर (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का त्वरित तथा सुरक्षित प्रसारण) प्रणाली

258क. भारत के सर्वोच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय/अंतिम आदेश/अंतरिम आदेश/जमानत आदेश/पुनरीक्षण तथा अन्य न्यायिक कार्यवाहियों में पारित आदेश की प्रत्येक ई-प्रमाणित प्रति, जो फास्टर द्वारा अधीनस्थ/विचारण न्यायालय और अन्य कर्तव्य धारकों को निष्पादन के लिए प्राप्त होगी, उनका वैसा ही प्रभाव होगा, जैसा कि पुनरीक्षण और अन्य न्यायिक कार्यवाही में पारित निर्णय/अंतिम आदेश/अंतरिम आदेश/जमानत आदेश/आदेश की मूल प्रतियों का होता है।”

हस्ता./—

(अरविन्द कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल.

Bilaspur, the 24th July 2023

NOTIFICATION

No. 9051/Rules/2023. – The High Court of Chhattisgarh, with approval of the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Rules and Orders (Criminal), namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

After Chapter 9, the following Chapter shall be inserted, namely:-

"Chapter-9(A)

Faster (Fast and Secure Transmission of Electronic Records) System

258A.- Every e-authenticated copy of Judgment /final order/interim order/bail order/order passed in revision and other judicial proceedings by Supreme Court of India, High Court of Chhattisgarh and Appellate/ Revisional Court, received by Subordinate /Trial Court and other duty holders for execution by FASTER will have the same effect as they were the original copies of the judgment/final order/interim order/bail order/order passed in revision and other judicial proceeding."

Sd/-

(Arvind Kumar Verma)
Registrar General.